

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 263034

पटना, दिनांक- 24/2/16

ग्रा0वि0-5/आधार (न्या0)-107-03/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी
विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/ सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- डब्लु0 पी0 (सी0) संख्या-494/2012 न्यायविद् के0एस0 पुत्तास्वामी (सेवानिवृत), बनाम, भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार कार्ड योजना हेतु दिनांक-11.08.2015 को पारित अंतरिम आदेश (Interim Order) के आलोक में प्राप्त दिशानिर्देश के अनुपालन के संबंध में ।

प्रसंग:- उप महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय जापन संख्या-13012/20/ 2012/Legal-UIDAI (Pt IV) दिनांक-09.01.2016


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों (प्रति संलग्न) के द्वारा डब्लु0 पी0 (सी0) संख्या-494/2012 न्यायविद् के0एस0 पुत्तास्वामी (सेवानिवृत), बनाम, भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.08.2015 को पारित अंतरिम आदेश (Interim Order) के आलोक में विषयाधीन कार्यालय जापन द्वारा आधार संख्या की गोपनीयता से संबंधित दिशानिर्देश संसूचित किया गया है, जिसे संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि विषयाधीन कार्यालय जापन द्वारा संसूचित दिशानिर्देश से सभी अधीनस्थ कार्यालयों को शीघ्र अवगत कराने तथा अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन


(प्रमोद कुमार बिहारी)
विशेष सचिव ।

जापांक- 263034

दिनांक- 24/2/16

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
कृपया अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को इससे अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

जापांक- 263034

दिनांक- 24/2/16

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि संलग्न कार्यालय जापन की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराया जाय ।


विशेष सचिव ।

Hon. Ramesh Dew

F. No. 13012/20/2012/Legal-UIDAI (Pt IV)

Government of India

Ministry of Communications & Information Technology

Department of Electronics and IT (DeitY)

Unique Identification Authority of India



मुख्य सचिव बिहार

3rd Floor, Tower - II, Jeevan Bharati Building
Connaught Circus, New Delhi - 110001

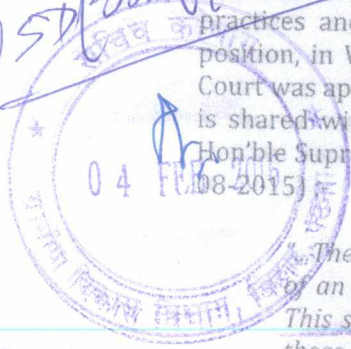
Dated 29th Jan, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Supreme Court order dated 11.08.2015 - Prohibition of Display of Aadhaar Number of residents in public domain

Important

050/600/ff/Bala



Biometric data - name, address, gender alongwith Aadhaar number has been recognised as a sensitive data and is a personal Information (PI), under Information Technology (Reasonable security practices and procedures and sensitive personal data or information) Rules, 2011. Based on this position, in W.P. No. 494 of 2012 & connected cases (known as "Aadhaar related matters") Supreme Court was apprised by the Ld Attorney General for India that no personal data of aadhaar card holder is shared with any other person or Authority by the respondents. This fact has been recorded by Hon'ble Supreme Court in its order dated 11.08.2015, as under (Page 14 of the Interim Order dated 11-

The learned Attorney General stated that the respondents do not share any personal information of an Aadhaar card holder through biometrics or otherwise with any other person or authority. This statement allays the apprehension for now, that there is a widespread breach of privacy of those to whom an Aadhaar card has been issued.."

2. Since Aadhaar numbers are being collected by various public as well as private agencies for delivery of services, it is hereby clarified that as per the above Supreme Court Order dated 11-08-2015, it is the responsibility of those agencies to:

- (a) Protect the identity of Aadhaar card holder by maintaining the necessary confidentiality of his Aadhaar number; and
- (b) To ensure that Aadhaar numbers are not posted, displayed, or made available in public domain such as internet, web, public notices etc. In case there is a requirement to publish a list of individuals by any department or any agency through a public notice, such list shall not contain Aadhaar numbers.

3. This issues with the approval of the DG & MD, UIDAI

YLP Rao
29/1/16

(Dr YLP Rao)
Dy Director General, UIDAI HQ
Phone: 011-23466815

To,

- All Secretaries to the Govt of India
- All Chief Secretaries of State Governments / UT Administrations
- All Dy Director Generals of UIDAI / Regional Offices of UIDAI
- All UIDAI Eco-system partners (Registrars, AUA/ASA/KUA/KSA etc.)

आजा जी
R
8/2/16

मुख्य सचिव का कार्यालय
308
08/02/16